स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए होगा तकनीक का इस्तेमाल

■ विनोद के शुक्ल

नई दिल्ली। एसएनबी

देश भर में स्कूल के छात्रों की ड्रॉपआउट संख्या के बारे में सही आंकड़े इकट्ठा करने के लिए सरकार तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव साझा किए हैं। एनसीपीसीआर ने एक पायलट योजना चलाकर इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस योजना को लागू करने में कोई अड़चन न आए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय समेत कई अन्य मंत्रालयों को इसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही गई है।

ड्रापआउट पर नजर रखने के लिए बनाई जा रही है योजना

ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसमें ऑफलाइन डाटा रजिस्टर होगा

इस योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश के सिंहस्थ मेले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयोग करके मेले को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया था। इसके लिए एक-एक बच्चे का आंकड़ा रखे जाने की योजना थी जिसे बाद में विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा पुस्करन मेले में लागू किया गया जो सफल रहा था। इस मेले को चाइल्ड फ्रेंडली बनाकर मेले में आए सभी बच्चों की जानकारी उन्हें एक बारकोडेड बैंड उपलब्ध कराकर रखी गई जिसमें बच्चे की सारी सूचना कम्प्यूटर में दर्ज थी। इसी सॉफ्टवेयर को अब स्कूल की उपस्थिति की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका प्रयोग बृहद स्तर पर करने की सरकार की योजना है।

फोन आधारित एप के जरिए छात्रों की उपस्थिति उनको उपलब्ध कराए गए परिचय पत्र में मौजूद बारकोड के माध्यम से दर्ज होगी। छात्रों के परिचय पत्र के बारकोड को फोन के माध्यम से पढ़ा जाएगा और हर रोज उनकी उपथिति दर्ज कराई जा सकेगी। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जो डाटा ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकेगा और ऑनलाइन होते ही डाटा अपडेट हो जाएगा। इस परिचय पत्र की कीमत लगभग 20 रुपए के आसपास होने की बात कही जा रही है। इस प्रयोग को झारखंड मे सबसे पहले वहां के विद्यालयों मे लागू किए जाने की मांग की गई है। इसे झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिलों के 10-10 विद्यालयों मे लागू किए जाने के लिए स्कूलों ने मांग की है जिसे कारपोरेट सोशल रिसपासिबिलिटी के तहत फंड उपलब्ध कराकर सरकार लागू करना चाहती है।

सरकार की योजना है कि बारकोडिंग तकनीकि के अलावा डिजिटल उपस्थिति जांच, वाइस डिटेक्सन और अन्य उपलब्ध तकनीकि का इस्तेमाल करके छात्रों की सही उपस्थिति का आकडा हासिल कर पाएगी। छात्रों की मिड डे मील के समय की उपस्थिति की जांच करके छात्रों की सही उपस्थिति का सही आकडा हासिल किए जाने का भी सरकार प्रयास करेगी।